



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2017/माघ 26, 1938
No. 43]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2017/MAGHA 26, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

प्रकरण संख्या ओ आई 07/2017

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “मोनोईसोप्रोपीलेमिन” (एमआईपीए) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

सं.14/46/2016-डीजीएडी.—मैसर्स एल्काईल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक/घरेलू उद्योग/याचिकादाता कहा गया है) ने यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदनपत्र/याचिका प्रस्तुत करके चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “मोनोईसोप्रोपीलेमिन” (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उन पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और अतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्वारा पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

क. घरेलू उद्योग और उसका आधार

3. यह याचिका घरेलू उद्योग के रूप में मेसर्स एल्काईल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। मेसर्स एल्काईल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तुओं की एकमात्र उत्पादक कंपनी है।

4. रिकार्ड पर उपलब्ध प्रमाण के अनुसार आवेदक कंपनी का उत्पादन घरेलू उत्पादन का "प्रमुख भाग" बनता है क्योंकि यह देश में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाली एकमात्र उत्पादक कंपनी है। इसलिए प्राधिकारी का यह निर्धारण है कि आवेदक कंपनी, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर पात्र घरेलू उद्योग बनती है और आवेदक कंपनी उपरोक्त नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार घरेलू उद्योग के आधार के मानदंड को पूरा करती है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

5. मौजूदा याचिका में विचाराधीन उत्पाद "मोनोईसोप्रोपीलेमिन" है, जिसे एमआईपीए भी कहा जाता है। एमआईपीए एक आर्गेनिक सम्मिश्रण है जो कि एक अमीन है। यह अमीन्स के लिए एक विशेष आधार होता है। यह अमोनिया जैसी गंध युक्त हाईग्रोस्कोपिक बेरंगा तरल पदार्थ होता है। इसका द्रवनांक -95.2° सी है और इसका क्वथनांक 32.4° सी है। यह जल में मिश्रणीय है। यह अत्यंत ज्वलनशील है, जिसका ज्वलनांक -37° सी होता है। इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसके तनुकृत रूप को जल में मिला कर एनहाईड्रस रूप से किया जाता है, जिसमें एमआईपीए का मिश्रण घट कर 70% रह जाता है। इसे वाणिज्यिक रूप से एनहाईड्रस के रूप में और 70% रूप में दोनों में बेचा जाता है, जो कि उसके अनुप्रयोग अथवा अंतःप्रयोग पर निर्भर करता है।

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के उप-शीर्ष 29211190 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आयात आंकड़ों का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ याचिकादाता ने आईबीआईएस, द्वितीयक स्रोत के अनुसार कारोबार-बार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ग. समान वस्तु

7. याचिकादाता ने यह दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा कि आवेदक ने निवेदन किया है घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से समान वस्तु है। उपभोक्ता इन दोनों उत्पादों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते और वे ऐसा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक ने यह भी दावा किया है कि आयातित उत्पाद और घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पाद, दोनों तकनीकी और

वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें नियमावली के अंतर्गत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी भारत में आवेदकों द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश/क्षेत्र से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तुओं को "समान वस्तु" मानते हैं।

घ. शामिल देश

8. मौजूदा जांच चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के आरोपित पाटन के बारे में है।

ङ. सामान्य मूल्य

9. याचिकादाताओं ने यह निवेदन किया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों से संबंधित विश्वसनीय सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य का अनुमान, उत्पादन की लागत के आधार पर लगाया गया है, जिसके लिए संबद्ध देशों में कच्चे माल की प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और प्रयोज्यताओं की लागत, घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागत को ध्यान में रखा गया है तथा जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ उचित लाभ को विधिवत् समायोजित किया गया है।

च. निर्यात कीमत

10. आवेदकों द्वारा द्वितीयक स्रोत, आईबीआईएस से प्राप्त किए गए कारोबार-बार आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश से भारत आयात कीमत के रूप में निर्यात कीमत का दावा किया गया है। कारखाना-गत स्तर पर निबल निर्यात कीमत का आकलन करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों को ध्यान में रख कर कीमत का समायोजन किया गया है।

छ. पाटन मार्जिन

11. सामान्य मूल्य की तुलना, कारखाना-गत स्तर पर निबल निर्यात कीमत के साथ की गई है। प्रथम दृष्टया ऐसे पर्याप्त प्रमाण विद्यमान हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य, कारखाना-गत निर्यात कीमत से बहुत अधिक है, जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन न्यूनतम से काफी अधिक होने का अनुमान है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

12. घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का मूल्यांकन करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने संपूर्ण रूप से तथा उत्पादन और खपत, कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने के संबंध में पाटित आयातों की बढ़ती हुई मात्रा के रूप में और उसके परिणामस्वरूप उत्पादन, बिक्रियों, बाजार के हिस्से और माल-सूचियों में गिरावट आने के रूप में उनके पड़ने वाले अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव के बारे में प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। इस पाटन-रोधी जांच को शुरू करने को न्यायोचित ढहराने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही "आर्थिक क्षति" के पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण विद्यमान हैं।

झ. जांच की अवधि

13. मौजूदा जांच की अवधि जुलाई, 2015 से सितंबर, 2016 (15 महीनों) तक की है। तथापि, क्षति अवधि में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच अवधि भी शामिल होगी।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संबद्ध सूचना प्रस्तुत करने तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली - 110001

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत अपने निवेदन नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता।

ट. समय-सीमा

16. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित 40 (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटन-रोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग की याचिका पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/निवेदनों के किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया जाता है, तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को, प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय वृत्तान्त की दो (02) प्रतियां और अगोपनीय वृत्तान्त की पांच (05) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाना क्यों संभव नहीं है।

21. अगोपनीय वृत्तान्त को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय वृत्तान्त की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विस्तृत विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्थक अगोपनीय वृत्तान्त के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है, जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय वृत्तान्त रखे गए हैं।

ढ. असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डा. इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2017

Case No. OI 07/2017

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports 'of Monoisopropylamine' (MIPA), originating in or exported from China PR

F. No. 14/46/2016-DGAD. — M/s. Alkyl Amines Chemicals Ltd (hereinafter referred to as the applicant/domestic industry/petitioner) have filed an application/petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the

Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty concerning imports of Monoisopropylamine (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

A. Domestic Industry & Standing

3. The petition has been filed M/s Alkyl Amines Chemicals Ltd by as the domestic industry and M/s Alkyl Amines Chemicals Ltd is the sole producers of the subject goods in India.

4. As per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes "a major proportion" of the domestic production since it is the sole producer of the subject goods in the Country. The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

B. Product under Consideration

5. The product under consideration in the present petition is "Monoisopropylamine", also known as MIPA. MIPA is an organic compound, an amine. It is a base, as typical for amines. It is a hygroscopic colorless liquid with ammonia-like odor. Its melting point is -95.2°C and its boiling point is 32.4°C . It is miscible with water. It is extremely flammable, with flash point at -37°C . It is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. MIPA is produced in anhydrous (99.5%). Diluted form is obtained by adding water to anhydrous form which reduces the concentration of MIPA to 70%. It is commercially sold both in anhydrous form and 70% form depending on the application or end use.

6. Product under consideration is classified under Chapter 29, under sub heading 29211190 of Customs Tariff Act, 1975. For the purpose of analyzing the imports data, the petitioner have relied upon transaction-wise import data as per IBIS, a secondary source.

C. Like Article

7. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject country and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicant, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicant has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicants in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country/territory.

D. Country involved

8. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR (referred to as the “subject country”).

E. Normal Value

9. The petitioners have submitted that in the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject countries the Normal values in the subject countries have been estimated on the basis of cost of production; taking into account prevailing international prices of raw materials and cost of utilities in subject countries, conversion costs of the domestic industry, duly adjusted on account of selling, general & administration expenses, plus reasonable profit.

F. Export Price

10. The export price has been claimed by the applicants as the weighted average import price from subject country based on the transaction-wise import data obtained from a secondary source, IBIS. Price adjustments have been made on account of Ocean Freight, Marine insurance, Commission, Inland Freight expenses, Port expenses and Bank charges to arrive at the net export price at ex-factory level.

G. Dumping Margin

11. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

H. Injury and Causal Link

12. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price undercutting, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of decline in production, sales, market share, inventories. There is sufficient prima facie evidence of the ‘material injury’ being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

I. Period of Investigation

13. The period of investigation for the present investigation is from July 2015 to September 2016 (15 months). The injury investigation period will however cover the periods 2013-14, 2014-15, 2015-16 and period of investigation.

J. Submission of information

14. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.**

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

K. Time limit

16. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation

L. Submission of Information on Non-Confidential basis

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.

20. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information

M. Inspection of Public File

24. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

N. Non-cooperation

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority